GEO IAS
It's about quality

27 June 2024

GEO Daily

Daily Current Affairs

GEO IAS

SOURCES

THE HINDU | The Indian EXPRESS JOURNALISM OF COURAGE | pib | PIB | live mint | THE FINANCIAL EXPRESS | ET ECONOMIC TIMES.COM

Date: 27 June 2024

Important News Articles

1. कोयला खनन से गंभीर श्वसन और त्वचा रोग होने का खतरा - द हिंदू
2. डमी FIR और पॉकेट गाइड के साथ पुलिस नए आपराधिक कानूनों पर स्विच करने के लिए तैयार- द हिंदू
3. भारत की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी बन्नेरघट्टा में खुली- द हिंदू
4. IISER तिरुपति ने मेथनॉल और पैराफॉर्मेल्डिहाइड से हाइड्रोजन उत्पादन विधि विकसित की- पीआईबी
5. केंद्रीय मंत्री ने CEL को 'मिनी रत्न' (श्रेणी-1) का दर्जा देने की घोषणा की- पीआईबी
6. चंद्रयान-4 के पुर्जे दो प्रक्षेपणों के लिए भेजे जाएंगे: इसरो प्रमुख

Editorials, Gists and Explainers

7. आंध्रप्रदेश में NDA की जीत से रियल एस्टेट सेक्टर में स्पष्टता आने की उम्मीद - द हिंदू
8. केंद्र इस वर्ष के अंत तक भारतीय मध्यस्थता परिषद (MCI) की स्थापना करेगा -- द प्रिंट
9. भारत में रूफटॉप सौर ऊर्जा योजना का कितना उपयोग हो रहा है? - द हिंदू
10. लोकसभा में विपक्ष के नेता की भूमिका - इंडियन एक्सप्रेस

Quick Look

1. अदन की खाड़ी
2. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO):
3. जैविक विविधता अधिनियम, 2002
4. वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग
5. आधिकारिक ऋणदाता समिति (OCC):

महत्वपूर्ण समाचार लेख

सामान्य अध्ययन II

1. कोयला खनन से गंभीर श्वसन और त्वचा रोग होने का खतरा - द हिंदू

प्रासंगिकता: स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधन से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित मुद्दे।

प्रीलिम्स टेकअवे
- कोयला खनन के प्रभाव

समाचार:
- नेशनल फाउंडेशन फॉर इंडिया द्वारा प्रकाशित एक सर्वेक्षण में कहा गया है कि कोयला खनन प्रदूषकों के लंबे समय तक संपर्क में रहने से व्यापक श्वसन और त्वचा संबंधी रोग हुए हैं।

मुख्य बिंदु:
- साक्षात्कार में शामिल कम से कम 65% प्रतिभागियों ने क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, तथा त्वचा संबंधी बीमारियों जैसे एक्जिमा, डर्मेटाइटिस और फंगल संक्रमण की शिकायत बताई।
- खदानों के निकट रहने वाले लोग अपेक्षाकृत अधिक असुरक्षित थे।
- धनबाद और रामगढ़, जहां ऐसे क्षेत्रों में अधिक लोग रहते हैं, वहां फेफड़े और श्वास संबंधी बीमारियों के साथ-साथ त्वचा संक्रमण के मामले भी अधिक हैं।
- दुनिया के कोयले से दूर जाने से कोयला-निर्भर क्षेत्रों में बड़ी संख्या में नौकरियां खत्म होने और आर्थिक मंदी आने की आशंका है।
- इसका सीधा असर न केवल कोयला खनिकों और श्रमिकों पर पड़ेगा, बल्कि व्यापक स्थानीय अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा।
- अध्ययन का व्यापक जोर 'न्यायसंगत परिवर्तन' की जांच करने पर था, अर्थात यह कि किस प्रकार कोयला खनन पर सीधे निर्भर लोगों को इन नौकरियों से प्रभावी और संवेदनशील तरीके से दूर किया जा सकता है।

भारत और नवीकरणीय ऊर्जा
- जबकि भारत ने वर्ष 2030 तक लगभग 500 गीगावाट बिजली या अपनी अनुमानित स्थापित क्षमता का लगभग आधा हिस्सा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त करने की प्रतिबद्धता जताई है, फिर भी यह उम्मीद है कि आने वाले दशकों में भारत में बिजली उत्पादन का मुख्य आधार कोयला ही रहेगा।
- भारत की स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता का लगभग आधा हिस्सा, या लगभग 205 गीगावाट, कोयला-चालित ताप विद्युत संयंत्र हैं।
- हालांकि, बदलाव की हवा चल रही है क्योंकि इस साल पहली बार, भारत द्वारा इस वर्ष की पहली तिमाही (जनवरी-मार्च) में जोड़े गए रिकॉर्ड 13.6 (गीगावाट) बिजली उत्पादन क्षमता में नवीकरणीय ऊर्जा का योगदान 71.5% रहा।
- जबकि कुल विद्युत क्षमता में कोयले की हिस्सेदारी (लिग्नाइट सहित) वर्ष 1960 के दशक के बाद पहली बार 50% से नीचे आ गयी।

2. डमी FIR और पॉकेट गाइड के साथ पुलिस नए आपराधिक कानूनों पर स्विच करने के लिए तैयार- द हिंदू

प्रासंगिकता: विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप तथा उनके डिजाइन और कार्यान्वयन से उत्पन्न मुद्दे।

प्रीलिम्स टेकअवे
- CCTNS
- BNS, 2023

समाचार:
- 1 जुलाई से नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन से पहले, अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम (CCTNS) में कम से कम 23 संशोधन किए गए हैं। यह एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसका उपयोग देश भर के 16,000 से अधिक पुलिस स्टेशनों द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के लिए किया जाता है।

मुख्य बिंदु:
- नए कानून के लागू होने से, FIR दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 154 के बजाय भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 173 के तहत दर्ज की जाएंगी।
- सभी राज्य इस पर सहमत थे और 1 जुलाई से नई प्रणाली को अपनाने के लिए तैयार थे।

+91-9477560001, +91-9477560002, +91-9477560005
info@geoias.com
www.geoias.com
BRANCH: Delhi Kolkata, Raipur, Patna | Head office: 641, Ramlal Kapoor Marg, Mukherjee Nagar, Delhi, 110009

- भारतीय न्याय संहिता (BNS) भारतीय दंड संहिता, 1860 का स्थान लेती है; भारतीय साक्ष्य (BS) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 का स्थान लेती है; तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 का स्थान लेती है।
- दिल्ली पुलिस, जो नए कानूनों के लिए प्रशिक्षण और शैक्षिक मॉड्यूल शुरू करने वाली देश भर की पहली पुलिस बलों में से एक है, का लक्ष्य अगस्त तक सभी 90,000 पुलिस कर्मियों को संवेदनशील बनाना है।
- उन्होंने कहा, "पुलिस अधिकारियों को नए प्रारूप का आदी बनाने के लिए डमी FIR दर्ज की जा रही हैं।
- हमने सभी स्तरों के लिए तैयार गणना के रूप में तीनों कानूनों को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करने वाली छोटी-छोटी पुस्तकें उपलब्ध करा दी हैं।
- सालों से इस्तेमाल हो रहे कानूनों की धाराएं बदली जा रही हैं, केस दर्ज करते समय किताबें काम आएंगी
- एक अन्य पुलिस अधिकारी ने कहा कि IPC और CrPC जैसे पुराने कानून अभी भी इस्तेमाल में रहेंगे। "अगर कोई मामला 1 जुलाई के बाद दर्ज किया जाता है, लेकिन अपराध उस तारीख से पहले हुआ है, तो इसे BNSS और IPC की संबंधित धाराओं के तहत दर्ज किया जाएगा।
- अदालत में मौजूदा मामले, जिनमें आरोपपत्र अभी दाखिल नहीं हुए हैं या जिनमें अभी सुनवाई चल रही है, पुरानी प्रणाली के तहत ही चलाए जाएंगे।
- CCTNS में पुराने और नए दोनों प्रावधान होंगे
- कुल 20 नये अपराध जोड़े गए हैं तथा 33 अपराधों के लिए कारावास की अवधि बढ़ा दी गई है।
- छह अपराधों के लिए सामुदायिक सेवा का दंड लागू किया गया है तथा 23 अपराधों के लिए अनिवार्य न्यूनतम सजा लागू की गई है।

सामान्य अध्ययन III

3. भारत की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी बन्नेरघट्टा में खुली- द हिंदू

प्रासंगिकता: संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और गिरावट, पर्यावरण प्रभाव आकलन

प्रीलिम्स टेकअवे
- बिग कैट्स
- बंनेर्घट्टा

समाचार:
- दक्षिण भारत की पहली और देश की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी का उद्घाटन कर्नाटक के बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान में किया गया।
- सफारी के लिए केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के दिशानिर्देशों के अनुसार, सफारी के लिए 20 हेक्टेयर क्षेत्र का सीमांकन कर बाड़ लगा दी गई है।

मुख्य बिंदु:
- खुले वन क्षेत्र में सफारी के लिए आठ तेंदुओं को छोड़ा गया है।
- बन्नेरघट्टा में स्वतंत्र रूप से विचरण करने वाले तेंदुओं (पेंथेरा पार्डस) की अच्छी आबादी रहती है, और इन शिकारियों पर प्रकाश डालना महत्वपूर्ण है।
- तेंदुआ सफारी क्षेत्र प्राकृतिक चट्टानी चट्टानों और अर्ध-पर्णपाती वनों से युक्त ऊबड़-खाबड़ भूभाग से बना है।
- अधिकारियों ने बताया कि हाल के दिनों में मानव-पशु संघर्ष में वृद्धि के कारण, पूरे कर्नाटक से बचाए गए कई तेंदुए के बच्चे पार्क में आते हैं।
- इन शावकों को तेंदुआ सफारी में ले जाया जाएगा, ताकि आगंतुकों को इन बड़ी बिल्लियों, बढ़ते मानव-पशु संघर्षों के कारणों और जानवरों की सुरक्षा के तरीकों के बारे में जानने में मदद मिल सके।
- अधिकारियों ने बताया कि सफारी क्षेत्र के भीतर चार एकड़ भूमि को सौर बाड़ लगाकर अलग कर दिया गया है, ताकि जानवरों को उनके नए वातावरण के अनुकूल ढलने में मदद मिल सके।

अन्य पहल
- कई नई पहलों की भी घोषणा की गई, जिनमें एक पुनर्निर्मित हाथी छुड़ाने केंद्र, तितली पार्क में एक शिशु देखभाल कक्ष, बच्चों के लिए खेल का मैदान, एक प्रवेश द्वार शामिल है, और उन्होंने इलेक्ट्रिक बग्गी और चिड़ियाघर प्रतिष्ठानों को भी हरी झंडी दिखाई।
- एक नर हाथी का बच्चा "स्वराज" और छह हमाद्रियास बबून भी सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए हैं।
- चिड़ियाघर और तितली पार्क के बीच संपर्क स्थापित करने के लिए स्काईवॉक भी विकसित किए जा रहे हैं।

4. IISER तिरुपति ने मेथनॉल और पैराफॉर्मेल्डिहाइड से हाइड्रोजन उत्पादन विधि विकसित की- पीआईबी

प्रीलिम्स टेकअवे
- हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था
- मेथनॉल

प्रासंगिकता: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में भारतीयों की उपलब्धियां; प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण और नई प्रौद्योगिकी का विकास।

समाचार:
- शोधकर्ताओं ने हल्की परिस्थितियों में मेथनॉल और पैराफॉर्मेल्डिहाइड के मिश्रण से हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करने की एक नवीन सिंथेटिक विधि विकसित की है।
- यह विधि विशेष रूप से प्रभावी साबित हुई है
  - एल्काइनों का एल्केनों में हाइड्रोजनीकरण और
  - यह संयोजन एक आशाजनक हाइड्रोजन वाहक हो सकता है, जो रासायनिक संश्लेषण और संधारणीय ऊर्जा समाधान में प्रगति का मार्ग प्रशस्त करेगा।
- जीवाश्म ईंधनों की तीव्र कमी ने वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों की खोज को बढ़ावा दिया है, जिससे संधारणीय और नवीकरणीय संसाधनों की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है।
- हाइड्रोजन गैस उत्पादन विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें ऊर्जा भंडारण, परिवहन और विभिन्न रासायनिक प्रक्रियाओं में जीवाश्म ईंधनों का स्थान लेने की क्षमता है।
- मेथनॉल और पैराफॉर्मेल्डिहाइड, दोनों का उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जाता है, तथा ये हाइड्रोजन वाहक के रूप में व्यवहार्य उम्मीदवार के रूप में उभरे हैं।
- उनकी प्रचुरता और व्यापक निर्माण उन्हें हाइड्रोजन के भंडारण और परिवहन के लिए मूल्यवान बनाता है, जो मुक्त हाइड्रोजन की तुलना में महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करता है।
- शोध में बेस या एक्टिवेटर की आवश्यकता के बिना मेथनॉल और पैराफॉर्मलडिहाइड से हाइड्रोजन का उत्पादन करने के लिए व्यावसायिक रूप से उपलब्ध निकल उत्प्रेरक का उपयोग किया गया है।
- इस कुशल उत्प्रेरक प्रणाली ने हल्की परिस्थितियों में उल्लेखनीय दक्षता प्रदर्शित की है, तथा उत्पन्न हाइड्रोजन को एल्काइनों के रासायनिक और स्टीरियो-चयनात्मक आंशिक स्थानांतरण हाइड्रोजनीकरण में सफलतापूर्वक नियोजित किया गया है।
- इस प्रक्रिया ने संवर्धित सिंथेटिक मूल्य वाले जैवसक्रिय अणुओं तक पहुँच को सक्षम किया।
- इस शोध को ANRF (पूर्ववर्ती SERB, जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST) का एक सांविधिक निकाय है) द्वारा समर्थित किया गया था।
- यह शोध, जिसे कैटालिसिस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पत्रिका में प्रकाशन के लिए स्वीकार किया गया है, COx-मुक्त हाइड्रोजन उत्पादन के लिए एक नया रास्ता खोलता है, तथा 'हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था' को आगे बढ़ाने में योगदान देता है।
- हाइड्रोजन वाहक के रूप में मेथनॉल और पैराफॉर्मेल्डिहाइड का उपयोग करने की क्षमता, बढ़ती वैश्विक ऊर्जा मांगों से उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करने की महत्वपूर्ण क्षमता प्रदान करती है।
- यह विकास संधारणीय ऊर्जा समाधान की खोज में एक महत्वपूर्ण कदम है।

5. केंद्रीय मंत्री ने CEL को 'मिनी रत्न' (श्रेणी-1) का दर्जा देने की घोषणा की- पीआईबी

प्रीलिम्स टेकअवे
- मिनी रत्न
- CEL

प्रासंगिकता: निवेश मॉडल

समाचार:
- सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (CEL) के स्वर्ण जयंती समारोह में उसे "मिनी रत्न" (श्रेणी-1) का दर्जा प्रदान किया गया।

मुख्य बिंदु:
- CEL घाटे में चल रही सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी से लाभांश देने वाली कंपनी में तब्दील हो गई है और यह लगातार तीसरा वर्ष है जब CEL ने भारत सरकार को लाभांश का भुगतान किया है, वह भी बढ़ती दर पर।
  - लगभग 58 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ प्राप्त हुआ।
- प्रधानमंत्री के अमृत काल विजन के अनुरूप, CEL का उद्देश्य प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण बढ़ाना और क्षमता निर्माण, कौशल विकास के माध्यम से विनिर्माण को बढ़ावा देना है।
- रक्षा, रेलवे, सुरक्षा, निगरानी और सौर ऊर्जा के क्षेत्र में CEL का योगदान स्वदेशी प्रौद्योगिकियों और विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ावा देने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है।

- उन्होंने आगे कहा, "स्मार्ट बोर्ड का उत्पादन शुरू करने से न केवल CEL के उत्पाद पोर्टफोलियो में विविधता आएगी, बल्कि देश के स्कूलों में स्मार्ट शिक्षा के कार्यान्वयन पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा।"
- कर्मचारी संलग्नता को मजबूत करने के लिए CEL प्रबंधन द्वारा उठाए गए नए कदमों के कारण पिछले कुछ वर्षों में उत्कृष्ट प्रदर्शन हुआ तथा पिछले वित्तीय वर्ष में सर्वकालिक उच्चतम उपलब्धि हासिल हुई।
- सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने मिनी रत्न (श्रेणी-1) का उच्चतर दर्जा प्रदान करने के लिए प्रदर्शन मापदंडों के सही बक्से पर टिक किया है।

6. चंद्रयान-4 के पुर्जे दो प्रक्षेपणों के लिए भेजे जाएंगे: इसरो प्रमुख

प्रासंगिकता: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में भारतीयों की उपलब्धियां; प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण और नई प्रौद्योगिकी का विकास।

प्रीलिम्स टेकअवे
- इसरो
- NGLV

समाचार:
- इसरो अध्यक्ष ने कहा कि चंद्रयान-4, जो चंद्रमा से नमूने लेकर आएगा, एक बार में प्रक्षेपित नहीं किया जाएगा, बल्कि इसके बजाय, अंतरिक्ष यान के विभिन्न भागों को दो प्रक्षेपणों के माध्यम से कक्षा में भेजा जाएगा, तथा चंद्रमा पर जाने से पहले अंतरिक्ष यान को अंतरिक्ष में ही जोड़ा जाएगा।

मुख्य बिंदु:
- चंद्रयान-4 की वहन क्षमता इसरो के वर्तमान सबसे शक्तिशाली रॉकेट की वहन क्षमता से भी अधिक होने की उम्मीद है।
- अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन और सभी पूर्ववर्ती समान सुविधाएं अंतरिक्ष में विभिन्न भागों को जोड़कर बनाई गई थीं।
- हालाँकि, यह संभवतः दुनिया में पहली बार होगा कि किसी अंतरिक्ष यान को टुकड़ों में प्रक्षेपित किया जाएगा और फिर अंतरिक्ष में उसे जोड़ा जाएगा।
- इसरो अंतरिक्ष में डॉकिंग क्षमता (अंतरिक्षयान के विभिन्न भागों को जोड़ना) की आवश्यकता पर काम कर रहा है, चाहे वह पृथ्वी हो या चंद्रमा।
- चंद्रमा से वापसी यात्रा पर अंतरिक्ष यान मॉड्यूलों का डॉकिंग एक बहुत ही नियमित प्रक्रिया है।
- अंतरिक्ष यान का एक हिस्सा मुख्य अंतरिक्ष यान से अलग होकर उतर जाता है जबकि दूसरा हिस्सा चंद्रमा की कक्षा में ही रहता है। जब उतरने वाला हिस्सा चंद्रमा की सतह से बाहर निकलता है, तो वह परिक्रमा करने वाले हिस्से से जुड़ जाता है और फिर से एक इकाई बन जाता है।
- चंद्रयान-4 मिशन के लिए विस्तृत अध्ययन, आंतरिक समीक्षा और लागत पर काम किया गया है, जिसे जल्द ही मंजूरी के लिए सरकार के पास भेजा जाएगा।
- यह उन चार परियोजना प्रस्तावों में से एक है, जिसे अंतरिक्ष एजेंसी अपने विजन 2047 के अनुरूप मंजूरी लेने की योजना बना रही है, जिसमें भारत द्वारा वर्ष 2035 तक अपना स्वयं का अंतरिक्ष स्टेशन बनाने और वर्ष 2040 तक चंद्रमा पर मानव भेजने की परिकल्पना की गई है।
- भारत का अंतरिक्ष स्टेशन, जिसका नाम भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन (BAS) है, भी अनेक प्रक्षेपणों के माध्यम से बुनियादी ढांचे के विभिन्न भागों को ले जाकर स्थापित किया जाएगा।
- "BAS के पहले खंड को LVM3 रॉकेट का उपयोग करके प्रक्षेपित किया जा सकता है क्योंकि यह आज उपलब्ध एकमात्र रॉकेट है और हमने निर्णय लिया है कि वर्ष 2028 तक हमें BAS का पहला प्रक्षेपण कर लेना चाहिए।
- इसरो प्रमुख ने कहा कि BAS के बाद के मॉड्यूल को या तो LVM3 के उन्नत संस्करण या नेक्स्ट जेनरेशन लॉन्च व्हीकल (NGLV) द्वारा उठाया जाएगा, जो एक भारी रॉकेट है जिसका विकास अभी चल रहा है। उन्होंने कहा कि NGLV के लिए पूर्ण डिजाइन और उत्पादन योजना तैयार कर ली गई है।
- इसरो बड़े और भारी NGLV के लिए एक नया लॉन्च कॉम्प्लेक्स भी बना रहा है। उन्होंने कहा कि मौजूदा लॉन्च कॉम्प्लेक्स 4,000 टन के रॉकेट के लिए पर्याप्त नहीं होगा। "इसके लिए एक बड़ी सुविधा और प्रसंस्करण क्षमता की आवश्यकता है।

एडिटोरियल, जिस्ट, एक्सप्लेनेर

7. आंध्रप्रदेश में NDA की जीत से रियल एस्टेट सेक्टर में स्पष्टता आने की उम्मीद - द हिंदू

प्रासंगिकता: कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना, संगठन और कार्यप्रणाली - सरकार के मंत्रालय और विभाग; दबाव समूह और औपचारिक/अनौपचारिक संघ और राजनीति में उनकी भूमिका।

समाचार:

- आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) की भारी जीत से रियल एस्टेट क्षेत्र में स्पष्टता आने की उम्मीद है।

मुख्य बिंदु

- रियल एस्टेट कारोबारी, जो 4 जून को आने वाले नतीजों का इंतजार कर रहे थे, अब राज्य के अन्य हिस्सों की तुलना में विशाखापत्तनम और अमरावती में निवेश और कारोबार की अधिक योजना बना रहे हैं।
- विशाखापत्तनम में निवेश में सुधार की संभावना है, जबकि अमरावती में रियल एस्टेट क्षेत्र में अचानक उछाल आने की उम्मीद है।
- अमरावती और विशाखापत्तनम में रियल एस्टेट कारोबारियों ने वर्ष 2014 से वर्ष 2023 के बीच सैकड़ों करोड़ रुपये का निवेश किया।
- वर्ष 2014 में संयुक्त आंध्र प्रदेश के विभाजन के तुरंत बाद, रियल एस्टेट कारोबारियों और निवेशकों ने शेष आंध्र प्रदेश में बेहतर अवसरों की तलाश शुरू कर दी है।
- उन्होंने इस उम्मीद में भारी निवेश किया कि हैदराबाद से अमरावती में राजधानी बनने के कारण आवास की मांग में अभूतपूर्व वृद्धि होगी।
- हालाँकि, अमरावती की राजधानी के निर्माण में अत्यधिक देरी हुई।
- इसकी आधारशिला अक्टूबर 2015 में रखी गई थी, लेकिन रियल एस्टेट बाजार में तेजी नहीं आई और रियल एस्टेट खिलाड़ी और निवेशक हैदराबाद लौट आए।
- इसी अवधि के दौरान आंध्र प्रदेश में सरकार बदल गई।
- नई पार्टी ने राज्य के विकास के लिए तीन राजधानियों का फार्मूला पेश किया।
- विशाखापत्तनम की ओर निवेश बढ़ने लगा, जिसे कार्यकारी राजधानी के रूप में प्रचारित किया गया।
- विशाखापत्तनम शहर के बाहरी इलाकों में मधुरवाड़ा, पेंडुर्थी, नायडू थोटा, सुजाता नगर, वेपगुंटा, नारवा और BHPV जैसे कई उद्यम शुरू हुए हैं, हालांकि वे विभिन्न कारणों से अधूरे रह गए हैं।
- यद्यपि पंजीकरण शुल्क मुख्य राजस्व स्रोतों में से एक है, फिर भी सरकार को सतत विकास के लिए रियल एस्टेट क्षेत्र के क्रमिक विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

8. केंद्र इस वर्ष के अंत तक भारतीय मध्यस्थता परिषद (MCI) की स्थापना करेगा -- द प्रिंट

प्रासंगिकता: भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाधनों का जुटाव, वृद्धि, विकास और रोजगार से संबंधित मुद्दे।

समाचार:

- सरकार द्वारा कारोबार को आसान बनाने के लिए इस वर्ष के अंत तक भारतीय मध्यस्थता परिषद (MCI) की स्थापना किए जाने की उम्मीद है।

मुख्य बिंदु

- इस पहल का उद्देश्य विवादों, विशेषकर व्यापार से संबंधित विवादों, का न्यायालय प्रणाली के बाहर समाधान सुगम बनाना है।
- इस वर्ष की शुरुआत में,IBBI द्वारा गठित एक समिति ने न्यायालय के बाहर विवादों के समाधान में तेजी लाने के लिए स्वैच्छिक मध्यस्थता ढांचे की शुरूआत का सुझाव दिया था।
- यह ढांचा न्यायालयों पर बोझ को भी कम कर सकता है, ठीक उसी तरह जैसे सरकार द्वारा 100 से अधिक कानूनी प्रावधानों को अपराधमुक्त करने का लक्ष्य इसी लक्ष्य को प्राप्त करना है।
- प्रस्तावित MCI की स्थापना मध्यस्थता अधिनियम के तहत की जाएगी, जिसे पिछले वर्ष अधिनियमित किया गया था।
- बिजनेस-डेली ने दावा किया है की राज्यसभा में किए गए खुलासे के अनुसार, इस अधिनियम के तहत मध्यस्थता कार्यवाही को शुरू होने के 180 दिनों के भीतर पूरा करना आवश्यक है
- परिषद मध्यस्थता के लिए नियम निर्धारित करेगी और मध्यस्थों को सशक्त बनाएगी।
- MCI मान्यता प्राप्त संस्थानों के माध्यम से मध्यस्थों की शिक्षा, मूल्यांकन और प्रमाणन की देखरेख करेगा। यह मध्यस्थों के आचरण के लिए मानक भी स्थापित करेगा और मध्यस्थता सेवा प्रदाताओं को मान्यता देगा।
- परिषद में एक अध्यक्ष और दो सदस्य होंगे, जो अधिनियम में निर्दिष्ट मध्यस्थता में विशेषज्ञता रखते होंगे।
- इसमें एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी और केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त वाणिज्य एवं उद्योग के किसी मान्यता प्राप्त निकाय का एक प्रतिनिधि भी शामिल होगा।

व्यवसाय में मध्यस्थता क्यों महत्वपूर्ण है?

- मध्यस्थता एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मध्यस्थ विवादित पक्षों को अदालत के बाहर समझौते तक पहुंचने में मदद करता है।
- न्यायालय के बाहर विवाद समाधान के अन्य तरीकों के विपरीत, मध्यस्थता के परिणामस्वरूप कोई बाध्यकारी निर्णय या निर्णय नहीं निकलता है।
- इसके बजाय, मध्यस्थ पक्षों को पारस्परिक रूप से संतोषजनक समझौते तक पहुंचने में सहायता करता है।
- पिछले वर्ष पारित मध्यस्थता अधिनियम के अनुसार, मध्यस्थता कार्यवाही प्रारम्भ होने के 180 दिनों के भीतर पूरी करना अनिवार्य है।
- इस कानून के तहत MCI की स्थापना की जाएगी।
- जैसा कि बताया गया है, परिषद मान्यता प्राप्त संस्थानों के माध्यम से मध्यस्थों के प्रशिक्षण और प्रमाणन के लिए भी जिम्मेदार होगी।
- वर्तमान में, मध्यस्थता आम तौर पर केवल तभी की जाती है जब कानून द्वारा इसकी आवश्यकता होती है, जैसे कि वर्ष 2015 के वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम के तहत, जो यह अनिवार्य करता है कि पक्ष अदालत में जाने से पहले मध्यस्थता का प्रयास करें

9. भारत में रूफटॉप सौर ऊर्जा योजना का कितना उपयोग हो रहा है? - द हिंदू

प्रासंगिकता: संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और गिरावट, पर्यावरण प्रभाव आकलन।

प्रसंग:

- भारत की स्थापित रूफटॉप सोलर (RTS) क्षमता में वर्ष 2023-2024 में 2.99 गीगावाट की वृद्धि हुई, जो एक साल में सबसे अधिक वृद्धि है।
- नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार, 31 मार्च तक भारत में कुल स्थापित RTS क्षमता 11.87 गीगावाट थी।

RTS कार्यक्रम

- भारत ने जनवरी 2010 में जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन का शुभारंभ किया।
- इसका मुख्य उद्देश्य तीन चरणों में 20 गीगावाट सौर ऊर्जा (RTS सहित) का उत्पादन करना था
- वर्ष 2015 में सरकार ने इस लक्ष्य को संशोधित कर वर्ष 2022 तक 100 गीगावाट कर दिया।
- दिसंबर 2022 में, भारत की स्थापित RTS क्षमता 7.5 गीगावाट थी और 40 गीगावाट लक्ष्य की समय सीमा वर्ष 2026 तक बढ़ा दी गई थी।
- भारत की समग्र RTS क्षमता लगभग 796 गीगावाट है।
- वर्ष 2030 तक 280 गीगावाट सौर घटक के साथ 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित करने के भारत के लक्ष्य को पूरा करने के लिए, अकेले RTS को वर्ष 2030 तक लगभग 100 गीगावाट का योगदान करने की आवश्यकता है।

राज्यों की स्थिति	RTS कैसे बढ़ सकता है?
• वर्ष 2024 में, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान की RTS क्षमताएं बड़ी छलांग लगा चुकी थीं, जबकि कुछ अन्य राज्य पीछे थे। • राजस्थान में RTS की संभावनाएं देश में सबसे अधिक हैं। स्वीकृतियों को सरल बनाने, वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करने और सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से RTS को बढ़ावा देने के इसके प्रयासों ने इस वृद्धि को बढ़ावा दिया है। • हालाँकि, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड सहित अन्य राज्यों को अभी भी अपनी RTS क्षमता का पूरी तरह से पता लगाना बाकी है। • उनकी चुनौतियों में नौकरशाही बाधाएं, अपर्याप्त बुनियादी ढांचा और सार्वजनिक जागरूकता की कमी शामिल हैं। **'प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना'** • यह एक प्रमुख पहल है, जिसका उद्देश्य एक करोड़ घरों में RTS प्रणाली स्थापित करना तथा उन्हें हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली उपलब्ध कराना है। • लक्षित घरों के लिए 2 किलोवाट के औसत सिस्टम आकार के परिणामस्वरूप कुल RTS क्षमता में 20 गीगावाट की वृद्धि होगी। • यह योजना उन्नत सौर प्रौद्योगिकियों, ऊर्जा भंडारण समाधानों और स्मार्ट ग्रिड अवसंरचना को अपनाने को भी प्रोत्साहित करती है।	• उपभोक्ताओं को अपने साथ जोड़ने के लिए जागरूकता पैदा करना महत्वपूर्ण है। • इसके अतिरिक्त, RTS को परिवारों के लिए आर्थिक रूप से व्यवहार्य होना चाहिए। • यद्यपि सरकारी सब्सिडी से मदद मिल रही है, फिर भी अनेक कम लागत वाले वित्तपोषण विकल्पों की आवश्यकता है। • हाल ही में RTS ऋण प्रदान करने वाले बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की संख्या में वृद्धि हुई है। • कम लागत वाले RTS ऋण तक पहुंच बाइक या कार ऋण प्राप्त करने जितनी आसान होनी चाहिए। • सौर प्रौद्योगिकी, ऊर्जा भंडारण समाधान और स्मार्ट-ग्रिड बुनियादी ढांचे में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने से लागत कम हो सकती है, प्रदर्शन में सुधार हो सकता है और RTS प्रणालियों की विश्वसनीयता बढ़ सकती है। • प्रशिक्षण कार्यक्रमों (जैसे वर्ष 2015 में शुरू किया गया 'सूर्यमित्र' सौर पीवी तकनीशियन कार्यक्रम) , व्यावसायिक पाठ्यक्रमों और कौशल विकास पहलों में निवेश से कुशल कार्यबल तैयार करने में मदद मिलेगी। • जैसे-जैसे योजना का कार्यान्वयन जोरों पर होगा, नेट-मीटरिंग विनियमों, ग्रिड-एकीकरण मानकों और भवन संहिताओं की समीक्षा की जानी चाहिए और उन्हें अद्यतन किया जाना चाहिए, ताकि उभरती चुनौतियों का समाधान करने और सुचारू कार्यान्वयन में सहायता मिल सके।

10. लोकसभा में विपक्ष के नेता की भूमिका - इंडियन एक्सप्रेस

प्रासंगिकता: संसद और राज्य विधानमंडल-संरचना, कार्यप्रणाली, कार्य संचालन, शक्तियाँ और विशेषाधिकार तथा इनसे उत्पन्न होने वाले मुद्दे।

प्रसंग:

- लोकसभा में 10 वर्षों से रिक्त पड़े विपक्ष के नेता के पद पर अंततः नियुक्ति हो गई है।

लोक सभा और राज्य सभा में विपक्ष के नेता	लोकसभा में विपक्ष के नेता: पद, भूमिका, जिम्मेदारियाँ
• विपक्ष के नेता की स्थिति को आधिकारिक तौर पर संसद में विपक्ष के नेताओं के वेतन और भत्ते अधिनियम, 1977 में वर्णित किया गया था। • अधिनियम में विपक्ष के नेता को, यथास्थिति, राज्य सभा या लोक सभा के सदस्य के रूप में वर्णित किया गया है, जो उस समय, उस सदन में सरकार के विपक्षी दल का नेता होता है, जिसकी संख्या सबसे अधिक होती है और जिसे राज्य सभा के सभापति या लोक सभा के अध्यक्ष द्वारा मान्यता दी जाती है। • कुछ स्वयंभू विशेषज्ञों द्वारा अक्सर एक रहस्यमय नियम का हवाला दिया जाता है, जिसके अनुसार किसी भी पार्टी को सदन में कम से कम 10 प्रतिशत सदस्यों का समर्थन प्राप्त होना चाहिए, तभी अध्यक्ष किसी व्यक्ति को विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता दे सकते हैं।	• विपक्ष का नेता अध्यक्ष के बाईं ओर अगली पंक्ति में बैठता है, और उसे औपचारिक अवसरों पर कुछ विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं, जैसे कि निर्वाचित अध्यक्ष को मंच तक ले जाना। • विपक्ष का नेता संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान भी अगली पंक्ति में सीट पाने का हकदार है। • विपक्ष के नेता का मुख्य कर्तव्य सदन में विपक्ष की आवाज़ बनना है। • वर्ष 2012 में संसद पर प्रकाशित एक आधिकारिक पुस्तिका में कहा गया है कि लोकसभा में विपक्ष के नेता को "एक छाया प्रधानमंत्री के रूप में माना जाता है, जिसके पास एक छाया मंत्रिमंडल होता है, जो सरकार के इस्तीफ़ा देने या सदन में हारने की स्थिति में प्रशासन संभालने के लिए तैयार रहता है।" • विपक्ष का नेता CBI के निदेशक, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और मुख्य सूचना आयुक्त, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों तथा लोकपाल जैसे प्रमुख पदों पर नियुक्ति के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली उच्चस्तरीय समितियों में विपक्ष का प्रतिनिधि होता है। • वरीयता क्रम में, लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष के नेता, केंद्रीय कैबिनेट मंत्रियों, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव, नीति आयोग के उपाध्यक्ष, पूर्व प्रधानमंत्रियों और मुख्यमंत्रियों के साथ सातवें स्थान पर आते हैं।

फैक्ट फटाफट

1. अदन की खाड़ी

- यह हिंद महासागर का विस्तार है, जो अरब प्रायद्वीप और अफ्रीकी महाद्वीप के बीच स्थित है।
- यह लाल सागर को अरब सागर और अंततः हिंद महासागर से जोड़ता है।
- इस खाड़ी का नाम यमन के तट पर स्थित बंदरगाह शहर "अदन" के नाम पर रखा गया है।
- यह दक्षिण में सोमालिया और सोकोत्रा द्वीपसमूह (यमन का हिस्सा), उत्तर में यमन, पूर्व में अरब सागर और पश्चिम में जिबूती से घिरा है।
- यह खाड़ी सोमाली सागर से तथा बाब अल-मन्देब जलडमरूमध्य द्वारा लाल सागर से जुड़ी हुई है।
- यह अरब सागर से अफ्रीका के हॉर्न और सोकोट्रा द्वीप समूह द्वारा अलग किया गया है।

2. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO)

- यह कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध अधिनियम, 1952 के अंतर्गत एक वैधानिक निकाय है।
- यह केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है।
- EPFO की संरचना:
- अधिनियम और इसकी सभी योजनाओं का प्रशासन एक त्रिपक्षीय बोर्ड द्वारा किया जाता है जिसे केन्द्रीय न्यासी बोर्ड कहा जाता है।
- बोर्ड में सरकार (केन्द्र और राज्य दोनों), नियोक्ता और कर्मचारियों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं।
- बोर्ड की अध्यक्षता भारत सरकार के केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री करते हैं।

3. जैविक विविधता अधिनियम, 2002

- यह अधिनियम 2002 में लागू किया गया था, इसका उद्देश्य जैविक संसाधनों का संरक्षण, इसके सतत उपयोग का प्रबंधन करना तथा स्थानीय समुदायों के साथ जैविक संसाधनों के उपयोग और ज्ञान से उत्पन्न लाभों को उचित और न्यायसंगत रूप से साझा करना है।
- इस अधिनियम में जैविक संसाधनों तक पहुंच को विनियमित करने के लिए तीन स्तरीय संरचना की परिकल्पना की गई थी: राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (NBA), राज्य जैव विविधता बोर्ड (SBB), जैव विविधता प्रबंधन समितियां (BMC) (स्थानीय स्तर पर)
- जैव विविधता अधिनियम, 2002 का जन्म जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (CBD) 1992 में निहित उद्देश्यों को साकार करने के भारत के प्रयास से हुआ था।

4. वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग

- आयोग एक वैधानिक निकाय है जिसका गठन पहली बार वर्ष 2020 में एक अध्यादेश द्वारा किया गया था।
- इसकी अध्यक्षता सचिव या मुख्य सचिव स्तर के सरकारी अधिकारी द्वारा की जाएगी।
- वह तीन वर्ष तक या 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक इस पद पर बने रहेंगे।
- इसमें पांच पदेन सदस्य भी होंगे जो या तो मुख्य सचिव होंगे या दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्यों में पर्यावरण संरक्षण से संबंधित विभाग के प्रभारी सचिव होंगे।
- CPCB, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और नीति आयोग के तकनीकी सदस्य
- वायु गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित अनुसंधान की जांच और संचालन करना, वायु प्रदूषण को रोकने और नियंत्रित करने के लिए कोड और दिशानिर्देश तैयार करना,
- निरीक्षण या विनियमन सहित मामलों पर निर्देश जारी करना जो संबंधित व्यक्ति या प्राधिकरण पर बाध्यकारी होगा।

5. आधिकारिक ऋणदाता समिति (OCC)

- इसका गठन पिछले वर्ष के आर्थिक संकट के दौरान श्रीलंका द्वारा ऋण उपचार के अनुरोध के प्रत्युत्तर में किया गया था।
- इसकी सह-अध्यक्षता भारत, जापान और फ्रांस द्वारा की जाती है, तथा ये पेरिस क्लब के अध्यक्ष हैं।
- श्रीलंका के सबसे बड़े द्विपक्षीय ऋणदाता चीन ने OCC में भाग न लेने का निर्णय लिया, लेकिन पर्यवेक्षक के रूप में बैठकों में भाग लिया।
- आधिकारिक ऋणदाता समिति (OCC) और श्रीलंका ने IMF के साथ विस्तारित निधि सुविधा (EFF) व्यवस्था के साथ संरेखित मुख्य मापदंडों पर सहमति व्यक्त की है।

GEO IAS It's about quality

प्रीलिम्स ट्रैक

Q1. भारत में नवीकरणीय ऊर्जा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. भारत की स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता का लगभग आधा हिस्सा कोयला-चालित ताप विद्युत संयंत्रों से आता है।
2. भारत की पहल, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) का उद्देश्य वैश्विक स्तर पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना है और इसकी स्थापना 2015 में की गई थी।
3. भारत में नवीकरणीय ऊर्जा की स्थापित क्षमता में पवन ऊर्जा का हिस्सा सबसे बड़ा है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

A. केवल 1 और 2
B. केवल 2 और 3
C. केवल 1 और 3
D. 1, 2 और 3

Q2. अपराध और अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क एवं सिस्टम (CCTNS) के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

1. CCTNS भारत सरकार की राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना (NeGP) के अंतर्गत एक परियोजना है।
2. CCTNS का प्राथमिक उद्देश्य देश भर के पुलिस स्टेशनों और अन्य पुलिस संगठनों के बीच डेटा और सूचना के संग्रहण, भंडारण, पुनर्प्राप्ति, विश्लेषण, स्थानांतरण और साझाकरण को सुविधाजनक बनाना है।
3. CCTNS को शुरू में गृह मंत्रालय (MHA) द्वारा क्रियान्वित किया गया था और बाद में प्रबंधन के लिए इसे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) को हस्तांतरित कर दिया गया था।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

A. केवल 1 और 2
B. केवल 2 और 3
C. केवल 1 और 3
D. 1, 2, और 3

Q3. निम्नलिखित में से राष्ट्रीय उद्यानों/वन्यजीव अभयारण्यों और उनके संबंधित राज्यों का कौन सा/से युग्म सही सुमेलित है/हैं?

1. ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभयारण्य: कर्नाटक
2. दांडेली वन्यजीव अभयारण्य : तमिलनाडु
3. जोगीमट्टी वन्यजीव अभयारण्य : आंध्र प्रदेश
4. नमदाफा राष्ट्रीय उद्यान : अरुणाचल प्रदेश

नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:

A. केवल 1 और 2
B. केवल 1 और 4
C. केवल 1, 2 और 3
D. केवल 2, 3 और 4

Q4. हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करके जल के इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से हाइड्रोजन का उत्पादन किया जा सकता है, जिससे यह एक हरित ईंधन बन जाता है।
2. हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से परिवहन और औद्योगिक प्रक्रियाओं के लिए ईंधन के रूप में हाइड्रोजन के उपयोग पर केंद्रित है।
3. भारत के राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन का उद्देश्य देश को हरित हाइड्रोजन उत्पादन और निर्यात का वैश्विक केंद्र बनाना है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

A. केवल 1 और 2
B. केवल 1, 2, और 3
C. केवल 1, 3, और 4
D. 1, 2, 3, और 4

Q5. भारत में मिनीरत्न और महारत्न कंपनियों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. महारत्न का दर्जा उन केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (CPSE) को दिया जाता है, जिनके पास नवरत्न और मिनीरत्न कंपनियों की तुलना में वित्तीय स्वायत्तता का स्तर अधिक होता है।
2. मिनीरत्न कंपनियों को दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, अर्थात् मिनीरत्न श्रेणी । और मिनीरत्न श्रेणी ।।।
3. केवल वे CPSE, जिनके पास कम से कम तीन वर्षों से नवरत्न का दर्जा है, महारत्न दर्जे के लिए विचार किए जाने के पात्र हैं।
4. मिनीरत्न और महारत्न दोनों ही कम्पनियां सरकार की मंजूरी के बिना एक निश्चित सीमा तक अपना निवेश कर सकती हैं।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

A. केवल 1 और 2
B. केवल 1, 2, और 3
C. केवल 2 और 4
D. 1, 2, 3, और 4

Q6. आदित्य--L1 मिशन के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. मिशन को सूर्य-पृथ्वी प्रणाली के लैग्रेंज बिंदु 2 (L2) के चारों ओर हेलो कक्षा में स्थापित किया जाएगा।
2. आदित्य – L1 का एक प्राथमिक उद्देश्य सौर कोरोना का अध्ययन करना है, जो सूर्य के वायुमंडल की सबसे बाहरी परत है।
3. इस मिशन का डिजाइन और प्रबंधन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) द्वारा नासा के सहयोग से किया गया है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

A. केवल एक
B. केवल दो
C. सभी तीनों
D. कोई नहीं

Q7. ऑपरेशन पोलो जो हाल ही में समाचारों में देखा गया था, निम्नलिखित में से किससे संबंधित है?

A. भारत का कारगिल युद्ध अभियान
B. सियाचिन ग्लेशियर पर पुनः कब्ज़ा करने के लिए भारत का अभियान
C. बांग्लादेश को आज़ाद कराने के लिए भारत का अभियान
D. हैदराबाद पर कब्ज़ा करने के लिए भारत का अभियान

Q8. निम्नलिखित कथन पर विचार करें

कथन I: ADR विवाद समाधान का एक तंत्र है जो गैर-प्रतिकूल है, अर्थात सभी के लिए सर्वोत्तम समाधान तक पहुंचने के लिए सहकारी रूप से एक साथ काम करना।

कथन II : एक गैर-बाध्यकारी प्रक्रिया जिसमें एक निष्पक्ष तीसरा पक्ष, मध्यस्थ, विवाद के पक्षों को विवाद के पारस्परिक रूप से संतोषजनक सहमत समाधान तक पहुंचने में सहायता करता है।

उपर्युक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

A. कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और कथन-II कथन-I का सही व्याख्या है
B. कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और कथन-II कथन-I का सही व्याख्या नहीं है
C. कथन-I सही है लेकिन कथन-II गलत है
D. कथन-I गलत है लेकिन कथन-II सही है

Q9. पीएम-सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. यह 10 करोड़ घरों में रूफ टॉप सोलर सिस्टम लगाने की एक प्रमुख पहल है
2. इससे परिवारों को हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलती है।
3. भारत ने 2022 तक 40 गीगावाट रूफटॉप सौर ऊर्जा स्थापित करने का लक्ष्य हासिल कर लिया है

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन गलत है/हैं?

A. केवल 1 और 2
B. केवल 2 और 3
C. केवल 1 और 3
D. 1, 2 और 3

Q10. भारत में विपक्ष के नेता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. लोक सभा में विपक्ष का नेता विपक्ष में सबसे बड़े दल का नेता होता है, जिसके पास सदन की कुल सदस्य संख्या का दसवां हिस्सा होता है।
2. विपक्ष के नेता को कैबिनेट मंत्री के समकक्ष दर्जा और सुविधाएं दी जाती हैं।
3. विपक्ष के नेता का पद भारत के संविधान में मान्यता प्राप्त है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

A. केवल 1 और 2
B. केवल 2 और 3
C. केवल 1 और 3
D. 1, 2 और 3

प्रीलिम्स ट्रैक उत्तर

उत्तर : 1 विकल्प A सही है

व्याख्या:

- भारत की स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता का लगभग आधा हिस्सा, या लगभग 205 गीगावाट, कोयला-संचालित ताप विद्युत संयंत्र हैं। **कथन 1 सही है।**
- अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) भारत द्वारा 2015 में स्थापित एक पहल है, जिसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना है। **कथन 2 सही है।**
- हाल के वर्षों में, सौर ऊर्जा ने भारत में अक्षय ऊर्जा स्थापित क्षमता का सबसे बड़ा हिस्सा बनाने के लिए पवन ऊर्जा को पीछे छोड़ दिया है। **कथन** 3 **गलत है।**

उत्तर : 2 विकल्प A सही है

व्याख्या:

- CCTNS वास्तव में भारत सरकार की राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना (NeGP), 2009 के तहत एक परियोजना है। **कथन 1 सही है**
- CCTNS का प्राथमिक उद्देश्य देश भर के पुलिस स्टेशनों और अन्य पुलिस संगठनों के बीच डेटा और सूचना के संग्रह, भंडारण, पुनर्प्राप्ति, विश्लेषण, हस्तांतरण और साझाकरण की सुविधा प्रदान करना है। **कथन 2 सही है**
- CCTNS हमेशा से गृह मंत्रालय (MHA) के अधीन रहा है और इसे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) को हस्तांतरित नहीं किया गया है। **कथन 3 गलत है**

उत्तर : 3 विकल्प B सही है

व्याख्या:

- ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभयारण्य कर्नाटक में है। **युग्म 1 सही है**
- दांडेली वन्यजीव अभयारण्य कर्नाटक में स्थित है, तमिलनाडु में नहीं। **युग्म 2 गलत है**
- जोगीमट्टी वन्यजीव अभयारण्य कर्नाटक में है। **युग्म 1 गलत है**
- नमदाफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। **युग्म 4 सही है**

उत्तर : 4 विकल्प D सही है

व्याख्या:

- नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करके पानी के इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से हाइड्रोजन का उत्पादन किया जा सकता है, जिससे यह एक हरित ईंधन बन जाता है। **कथन 1 सही है** ।
- हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से परिवहन और औद्योगिक प्रक्रियाओं के लिए ईंधन के रूप में हाइड्रोजन का उपयोग करने पर केंद्रित है। **कथन 2 सही है।**
- भारत के राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन का उद्देश्य देश को हरित हाइड्रोजन उत्पादन और निर्यात का वैश्विक केंद्र बनाना है। **कथन 3 सही है।**

उत्तर : 5 विकल्प D सही है

व्याख्या

- महारत्न का दर्जा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (CPSE) को दिया जाता है, जिनके पास नवरत्न और मिनीरत्न कंपनियों की तुलना में वित्तीय स्वायत्तता का स्तर अधिक होता है। **कथन 1 सही है।**
- मिनीरत्न कंपनियों को दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है, अर्थात् मिनीरत्न श्रेणी । और मिनीरत्न श्रेणी ।।। यह **कथन 2 सही है।**
- केवल वे CPSE जिनके पास कम से कम तीन वर्षों से नवरत्न का दर्जा है, महारत्न का दर्जा पाने के लिए पात्र हैं। **कथन 3 सही है।**
- मिनीरत्न और महारत्न दोनों कंपनियां सरकार की मंजूरी के बिना एक निश्चित सीमा तक अपना निवेश कर सकती हैं। **कथन 4 सही है** ।

उत्तर : 6 विकल्प A सही है

व्याख्या:

- मिशन को सूर्य-पृथ्वी प्रणाली के लैग्रेंज बिंदु 1 (L1) के चारों ओर एक हेलो कक्षा में रखा जाएगा। **यह कथन गलत है।**
- आदित्य-एल1 का एक प्राथमिक उद्देश्य सौर कोरोना का अध्ययन करना है, जो सूर्य के वायुमंडल की सबसे बाहरी परत है। **यह कथन सही है।**
- इस मिशन को नासा के सहयोग से भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) द्वारा डिजाइन और प्रबंधित किया गया है। यह कथन गलत है। आदित्य-एल1 मुख्य रूप से नासा के सहयोग के बिना इसरो का एक मिशन है।

उत्तर : 7 उत्तर: विकल्प D सही है

व्याख्या

- हैदराबाद राज्य निज़ाम के अधीन था जिसमें वर्तमान तेलंगाना, महाराष्ट्र का मराठवाड़ा क्षेत्र और कर्नाटक के कई क्षेत्र शामिल थे।
- हैदराबाद के निज़ाम को अपनी संप्रभुता बनाए रखने की उम्मीद थी और उन्होंने आज़ादी के बाद भारत में विलय के विचार का विरोध किया। हैदराबाद रियासत के आखिरी निज़ाम उस्मान अली खान आसफ़ जाह VII ने हैदराबाद को एक संप्रभु राज्य घोषित कर दिया और इससे तनाव बढ़ गया और सांप्रदायिक झड़पें हुईं।
- भारत सरकार नहीं चाहती थी कि हैदराबाद स्वतंत्र रहे, क्योंकि उसे डर था कि इससे देश के टुकड़े-टुकड़े हो जायेंगे।
- तत्कालीन गृह मंत्री सरदार पटेल ने स्वतंत्र हैदराबाद की अवधारणा को "भारत के हृदय में एक अल्सर बताया था, जिसे शल्य चिकित्सा द्वारा निकालने की आवश्यकता थी।"
- इसलिए, भारत ने हैदराबाद पर कब्ज़ा करने का फ़ैसला किया और इस अभियान का नाम "ऑपरेशन पोलो" रखा। 13 सितंबर, 1948 को भारतीय सेना ने हैदराबाद पर हमला किया। पाँच दिनों की लड़ाई में, भारतीय सेना ने हैदराबाद पर कब्ज़ा कर लिया और निज़ाम को निर्णायक रूप से हराकर इसे पूरी तरह से भारतीय क्षेत्र में मिला लिया।

उत्तर : 8 विकल्प B सही है

व्याख्या

- **मध्यस्थता करना:**
- विवाद को मध्यस्थ न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, जो विवाद पर निर्णय (एक "निर्णय") देता है, जो अधिकांशतः पक्षों पर बाध्यकारी होता है।
- सुलह:
- एक गैर-बाध्यकारी प्रक्रिया जिसमें एक निष्पक्ष तृतीय पक्ष, मध्यस्थ, विवाद के पक्षों को विवाद के पारस्परिक रूप से संतोषजनक सहमत समाधान तक पहुंचने में सहायता करता है।
- **मध्यस्थता:**
- मध्यस्थता में, एक निष्पक्ष व्यक्ति जिसे "मध्यस्थ" कहा जाता है, पक्षों को विवाद के पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान तक पहुंचने में मदद करता है।

उत्तर : 9 विकल्प C सही है।

व्याख्या:

'प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना'

- यह एक करोड़ घरों में आरटीएस प्रणाली लगाने की प्रमुख पहल है। **कथन 1 गलत है।**
- इसका उद्देश्य हर महीने घरों को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देना भी है। **कथन 2 सही है।**
- भारत ने 2022 तक 40 गीगावाट की छत सौर ऊर्जा स्थापित करने का लक्ष्य रखा था, लेकिन अब तक केवल 12 गीगावाट ही हासिल किया जा सका है। **कथन 3 गलत है।**

उत्तर : 10 विकल्प A सही है

व्याख्या:

- लोकसभा में विपक्ष का नेता वास्तव में विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी का नेता होता है, और इस रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए, पार्टी के पास सदन की कुल ताकत का कम से कम दसवां हिस्सा होना चाहिए। **कथन 1 सही है।**
- विपक्ष के नेता को कैबिनेट मंत्री के बराबर का दर्जा और सुविधाएं दी जाती हैं। **कथन 2 सही है।**
- भारत के संविधान में विपक्ष के नेता की स्थिति का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन यह एक वैधानिक स्थिति है, जो संसद अधिनियम, 1977 में विपक्ष के नेताओं के वेतन और भत्ते के तहत प्रदान की गई है। **कथन 3 गलत है।**

GEO IAS

It's about quality

ABOUT US

GEO IAS is the best institute for civil services in India for providing top quality teaching and materials, offering you most optimum path for your success in Civil Services exam. Our aim is to provide quality training with an affordable fee structure. Our uniquely designed course make us the best institute for UPSC to crack the exam in one go. We have a dedicated team of experienced and young teachers and counsellors who make sure that every student who joins the institute, must get customized way of preparation which matches with student's learning style.
The only institute of UPSC in India which has 3 AI enabled Mobile apps. We believe in Smart way of teaching and learning. The classes are available in offline as well as in online mode. We take the help of animation so that you may visualize the lectures. Unlimited tests for prelims and mains with solution in both form (Hard copy and soft copy). We have the set of 15 lac mcqs on each topic. We provide daily news analysis, Highlighted news paper and links of important Sansad TV shows. The institute has best success rate with more than 230 students have cleared the exam. HIGHEST RATED INSTITUTE as per GOOGLE, SULEKHA and JUST DIAL and the magazine on civil services

+91-9477560001 /002/005

BRANCH: Delhi Kolkata, Raipur, Patna | HEAD OFFICE: 641, Ramlal Kapoor Marg, Mukherjee Nagar, Delhi, 110009

info@geoias.com

www.geoias.com